

सप्तऋषि

बजट की सात प्राथमिकताएं

क्षमता को उजागर करना

100 प्रयोगशालाएं बनेंगी, 5जी सेवा एप विकास के लिए।
राष्ट्रीय डाटा रासन नीति • ई-कोर्ट का तीसरा चरण • धियाद से विश्वास योजना।

हरित विकास

10,000

बायो इनपुट संसाधन केंद्र शुरू होंगे। किसानों को प्राकृतिक कृषि में मदद।

युवा शक्ति

पीएमकेवीवाई 4.0 शुरू... कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग जैसे पाठ्यक्रम शामिल होंगे। राज्यों में युनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे।

वित्तीय क्षेत्र

2,00,000

करोड़ रुपये की कुल ऋण गारंटी एमएसएमई के लिए। इस बजट में नौ हजार करोड़ का प्रावधान

समावेशी विकास

20,00,000

करोड़ रुपये कृषि व सहकारिता में ऋण बांटने का लक्ष्य। स्टार्टअप व भंडारण को बढ़ावा।

आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचना

5,943

करोड़ रुपये एकलव्य स्कूलों को। पीएम पीवीटीजी योजना शुरू होगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर व विनिवेश

10,00,000

करोड़ रुपये पूंजीगत निवेश खर्च। पिछले साल से 33% ज्यादा।



अमृत काल... प्रौद्योगिकी संचालित व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए **तीन दृष्टिकोण**

1 युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर।

2 रोजगार सृजन को मजबूत गति देना

3 सुदृढ़-स्थिर वृहद् आर्थिक वातावरण

निर्मला सीतारमण का 5वां बजट : रोजगार सृजन के लिए सरकारी खर्च पर भरोसा, बुनियादी ढांचे पर खर्च होंगे 10 लाख करोड़ रुपये

89,155

करोड़ स्वास्थ्य मंत्रालय को

- पिछले साल 83 हजार करोड़ था
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन।

रक्षा : 5.94 लाख करोड़ रुपये

पिछले साल 5.25 लाख करोड़

ई-न्यायालय : 7,000 करोड़

- न्यायिक प्रशासन में दक्षता लाने के लिए ई-न्यायालय का तीसरा चरण शुरू होगा।



पर्यटन : देखो अपना देश मुहिम

- घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'देखो अपना देश मुहिम' शुरू की जाएगी। इसके तहत 50 पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी।

अग्निवीरों की राशि कर मुक्त

- अग्निवीर कॉर्पस फंड ईईईई श्रेणी में आएगा। इनका योगदान कर मुक्त होगा। इस पर मिलने वाले व्याज पर कर नहीं लगेगा। आखिर में जब पूरी राशि मिलेगी, उस पर भी कोई कर नहीं।
- 3.50 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चल रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षक एवं सहायक कर्मी नियुक्त होंगे।



1.97

लाख रुपये हो गई प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से ज्यादा बढ़कर

126

लाख करोड़ रुपये के 7,400 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए यूपीआई के जरिये 2022 में



कृषि : 1.25 लाख करोड़ रुपये कृषि एवं किसान कल्याण के लिए (पिछले साल 1,32,513 करोड़ था)

- भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा।
- मनरेगा : 60 हजार करोड़ खर्च होंगे। (पिछले साल 73 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था।)

सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन : 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य। जनजातीय क्षेत्र में सात करोड़ लोगों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण।

1:28 घंटे में पेश हुआ बजट। निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण।

हौसले बुलंद



बुनियादी ढांचा : पूंजीगत खर्च 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़। 50 एयरपोर्ट, हेलिपोर्ट, एयरड्रॉम बनेंगे। 100 नए प्रोजेक्ट, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान। इनसे सड़क, रेल, जहाज और विमान परिवहन से जुड़े क्षेत्र उत्साहित हैं। निवेशकों को भी बेहतर रिटर्न की उम्मीद। सीमेंट और मेटल क्षेत्र को भी लाभ।

मध्य वर्ग : 7 लाख रुपये तक आयकर न होने से बड़ी राहत। मध्य वर्ग की नतीर उपभोक्ता खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। बाजार में ज्यादा पैसा आएगा।

कृषि : उच्च-मूल्य वाली बागवानी में 2,200 करोड़ का निवेश। स्टार्टअप के लिए कृषि गतिवर्धक कोष। एग्रो-इंडस्ट्री व फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप को प्रेरणा मिलेगी।

पर्यटन : घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 जगहों विकसित होंगी। एप बनेंगे। होटल व टिकटिंग कंपनियों के लिए नए मौके।

भारतीय कार कंपनियां : हरित प्रगति के चलते लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन से जुड़ी चीजें सीमा शुल्क से बाहर। ईवी कंपनियों व बैटरी उत्पादकों को लाभ। ई-कार और टोपडिया वाहन तीन फीसदी तक सस्ते होंगे।

बढ़ी चिंता



बीमा क्षेत्र : 5 लाख से ज्यादा के प्रीमियम पर टैक्स घोषणा से प्रमुख बीमा कंपनियों के शेयर 5 से साढ़े 11% तक गिरे।

आभूषण : सोने पर पिछले साल जुलाई में बढ़ा आयात कर कम न होने और लेव में होना बनाने के लिए शोध की घोषणा के बाद आभूषण कंपनियों के शेयर 5% तक नीचे।

तेल कंपनियां : सरकारी तेल कंपनियों को उम्मीद थी कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम रखने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई होगी। राहत नहीं मिली, तो तेल कंपनियों के शेयर गिरे।

विदेशी कार कंपनियां : विदेश में बनी 40 हजार डॉलर से महंगी कारों पर उत्पाद शुल्क 60 से बढ़ाकर 70 फीसदी हुआ। इससे विदेशी कारें महंगी होंगी।

ये का लाभ

लाख की कमाई : लाख वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये न लगेगा, जो पहले 7 लाख रुपये था। 37 हजार रुपये बचत होगी।

कर स्लैब

तक	0%
	5%
	10%
	15%
	20%
यादा	30%

घन

घन वस्त्र की कीमतें बढ़ेंगी।

किस

किस की कीमतें बढ़ेंगी।

किस

किस की कीमतें बढ़ेंगी।

किस

किस की कीमतें बढ़ेंगी।

के विशेषज्ञों की जुबानी



अनंद मोहन, निरंकर सिंह, के.सुजाता राव, नितिन गोखले

विशेष 10 पेज

टेक्स	सियासत
प्रगति	प्रवाह
खेती-किसानी	बजट में यूपी
उद्यम	
परिवहन-रक्षा	
महिला-संरक्षण	
युवा	

मजेदार लम्हा

स्कैप नीति का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री सीतारमण के मुंह से निकल गया- ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल हटाए जाएंगे। सदन में हंसी की फुहारें छुटीं, तो संभली। फिर बोली-सारी... सारी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएंगे।